रणजीत टाइम्स

इंदौर

शुक्रवार, 5 जून, 2026

वर्ष 02 | अंक 136 कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

पश्चिम बंगाल में अटकी रेल परियोजनाओं पर मंथन करेंगे अश्विनी वैष्णव, शनिवार को करेंगे समीक्षा बैठक

केंद्रीय रेल मंत्री शनिवार को के दौरे पर जाएंगे, जहां वे राज्य में लंबित और रुकी हुई रेल परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करेंगे। दौरे के दौरान रेल मंत्री विभिन्न रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, भूमि अधिग्रहण, प्रशासनिक मंजूरियों और निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। बैठक में परियोजनाओं को गति देने और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए आवश्यक कदमों पर भी विचार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं लंबे समय से विभिन्न कारणों से प्रभावित रही हैं। केंद्र सरकार इन परियोजनाओं को जल्द पूरा कर रेल संपर्क, माल परिवहन और यात्री सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दे रही है। रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली इस समीक्षा बैठक को राज्य के बुनियादी ढांचे और रेल नेटवर्क के विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गुजरात-दमन पर मेहरबान मोदी!

22 हजार करोड़ से ज्यादा की सौगात विकास परियोजनाओं की बरसात

सूरत से दमन तक विकास का मेगा रोड शो, अस्पताल, एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। यह दौरा केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि विकास और बुनियादी ढांचे को लेकर केंद्र सरकार के विजन का बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है।

सूरत में प्रधानमंत्री लगभग 18,800 करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क, बिजली, औद्योगिक और जनकल्याण से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास

इसके साथ ही वे 200 बिस्तरों वाले आधुनिक ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे, जिससे लाखों श्रमिक परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा निवेश देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री आधुनिक बिजली वितरण प्रणाली के उन्नयन तथा दाहेज पेट्रोलियम परिसर में उन्नत अपशिष्ट निपटान और उपचार सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे।

सरकार का दावा है

औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और पर्यावरणीय प्रबंधन भी मजबूत होगा

शाम को प्रधानमंत्री दमन पहुंचेंगे, जहां लगभग 2,970 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इनमें स्वास्थ्य सेवाएं, नागरिक उड्डयन, पर्यटन, संपर्क, बुनियादी ढांचा और जनकल्याण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा लगभग 1,340 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे

इनमें सबसे महत्वपूर्ण "नमो एयरपोर्ट" का नया टर्मिनल भवन और "नमो अस्पताल" शामिल हैं। नया टर्मिनल क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करेगा और पर्यटन व व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राजनीतिक जानकारों का मानना है

गुजरात और दमन में विकास परियोजनाओं की यह श्रृंखला आगामी वर्षों की आर्थिक रणनीति और बुनियादी ढांचे के विस्तार का महत्वपूर्ण संकेत है। सरकार इसे "विकसित भारत" अभियान की दिशा में बड़ा कदम बता रही है।

शिलांग में पूर्वोत्तर के विकास का रोडमैप तय करेंगे अमित शाह

'नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान-2047' पर होगी बड़ी चर्चा

मेघालय की राजधानी Shillong में आज केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में पूर्वोत्तर भारत के विकास से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ भविष्य की विकास रणनीति पर व्यापक चर्चा होगी।

बैठक का मुख्य आकर्षण 'नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान-2047' रहेगा, जिसके माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र को वर्ष 2047 तक देश के सबसे विकसित और सशक्त क्षेत्रों में शामिल करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बैठक में पर्यटन, कृषि एवं बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, सड़क एवं रेल संपर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में चल रही योजनाओं और नई संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

इस उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री Jyotiraditya Scindia, राज्य मंत्री Sukanta Majumdar, पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद के सदस्य तथा केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर को "अष्टलक्ष्मी" के रूप में विकसित करने की नीति पर काम कर रही है। ऐसे में यह बैठक क्षेत्र में निवेश, रोजगार, पर्यटन और कनेक्टिविटी को नई गति देने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सत्र में लिए जाने वाले निर्णय पूर्वोत्तर भारत के विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

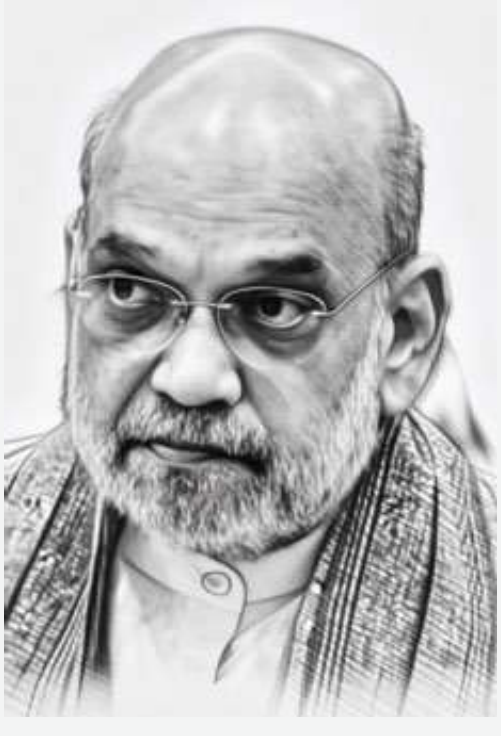

सूखे की मार, दुनिया लाचार! एशिया में नहीं हो रही बुवाई, मंडरा रहा वैश्विक खाद्य संकट

बारिश ने तोड़ा किसानों का भरोसा, खेत सूने और बाजार में बढ़ी महंगाई की आशंका

एशिया के कई देशों में सूखे और अनियमित मौसम ने कृषि व्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है।

पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण किसानों को फसलों की बुवाई टालनी पड़ रही है, जिससे वैश्विक खाद्य आपूर्ति पर दबाव बढ़ने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले हफ्तों में मौसम नहीं सुधरा तो दुनिया को नए खाद्य संकट और महंगाई की बड़ी लहर का सामना करना पड़ सकता है।

भारत से चीन तक चिंता

एशिया दुनिया की बड़ी कृषि अर्थव्यवस्थाओं का केंद्र है। भारत, चीन, थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में धान, गेहूं और अन्य खाद्यान्न फसलों की बुवाई मौसम पर निर्भर करती है। लेकिन इस बार कई इलाकों में बारिश सामान्य से कम होने के कारण किसान इंतजार की स्थिति में हैं।

घट सकता है उत्पादन

विशेषज्ञों का कहना है कि बुवाई में देरी का सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। यदि फसल चक्र प्रभावित हुआ तो चावल, गेहूं, मक्का और खाद्य तेलों की उपलब्धता कम हो सकती है। इसका असर केवल एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भर के खाद्य बाजारों में कीमतें बढ़ सकती हैं।

गरीब देशों पर सबसे बड़ा खतरा

खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि का सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ेगा जो पहले से आर्थिक संकट और खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं। अफ्रीका और एशिया के कई गरीब देशों में खाद्य आयात महंगा हो सकता है, जिससे करोड़ों लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो सकता है।

जलवायु परिवर्तन बना बड़ी चुनौती

मौसम विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़ और अत्यधिक तापमान जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसका सबसे बड़ा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है, जो दुनिया की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ माना जाता है।

दुनिया के सामने बड़ा सवाल

यदि आने वाले महीनों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई और फसल उत्पादन घटा, तो दुनिया को एक बार फिर खाद्य महंगाई, आपूर्ति संकट और भूख की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

एक वृक्ष, अनेक लाभ

अभ्यास मंडल ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश...

इंदौर। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में अभ्यास मंडल परिवार द्वारा आर.पी.एल. माहेश्वरी कॉलेज परिसर में नीम वृक्षारोपण एवं पर्यावरण जनजागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉ. मालासिंह ठाकुर ने अभ्यास मंडल का परिचय देते हुए संस्था द्वारा शिक्षा, समाजसेवा एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि प्रकृति के साथ संतुलित जीवन ही मानवता के सुरक्षित भविष्य का आधार है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रबंधन के श्री रामअवतार जाजू, डॉ. वीणा सोनी तथा अभ्यास मंडल के अध्यक्ष श्री रामेश्वर गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने पर्यावरणीय चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया।

कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण की शपथ डॉ. स्वप्निल व्यास ने दिलवाई। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉ. जयकिशन साहू ने स्वागत भाषण देते हुए उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। नीम वृक्षों के औषधीय, पर्यावरणीय एवं सामाजिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री किशनलाल सोमानी ने कहा कि नीम भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण वृक्ष है, जो वायु शुद्धिकरण के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। कार्यक्रम के दौरान परिसर में नीम के पौधों का रोपण किया गया तथा सभी उपस्थितजनों ने वृक्षों के संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. चेतन जोशी ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन डॉ. विकास जोशी ने माना।

कार्यक्रम के संयोजक श्री एन.के. उपाध्याय थे। इस अवसर पर सी.बी. सिंह, लव शारदा, देवेंद्र बाहेती, हरेराम वाजपेयी, नूर मोह कुरैशी,वैशाली खरे, मुरली खंडेलवाल, शफी शेख, यश जायसवाल, सुनील व्यास,, प्रणीता दीक्षित, सुनील कुमार चौधरी,शरद सोमपुरकर सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक, पर्यावरण प्रेमी एवं महाविद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

मानसून से पहले निगम की बड़ी तैयारी, शहरभर में 19 हजार स्टार्म वाटर चेंबरों की होगी सफाई

इंदौर। आगामी मानसून को देखते हुए नगर निगम ने शहर को जलभराव की समस्या से बचाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में नगर निगम के जनकार्य विभाग ने शहरभर में बिछी स्टार्म वाटर लाइन के लगभग 19 हजार चेंबरों की सफाई के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। निगम का लक्ष्य 13 जून तक सभी चेंबरों की सफाई का कार्य पूर्ण करना है, ताकि बारिश के दौरान पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके और नागरिकों को जलभराव जैसी परेशानियों का सामना न करना पड़े।

हर वर्ष मानसून के दौरान शहर के कई हिस्सों में नालियों और स्टार्म वाटर लाइनों में जमा गाद, प्लास्टिक, कचरा और अन्य अवरोधों के कारण पानी की निकासी प्रभावित होती है। इसके परिणामस्वरूप सड़कों पर पानी भर जाता है, यातायात बाधित होता है और आम नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस बार नगर निगम ने बारिश शुरू होने से पहले ही व्यापक सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

नगर निगम के जनकार्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार शहर के सभी 22 जोनल कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थापित स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रत्येक चेंबर की सफाई कर उसमें जमा गाद और कचरे को निकाला जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि समय रहते इन चेंबरों की सफाई नहीं की जाए तो बारिश के दौरान पानी का प्रवाह बाधित हो सकता है और कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

इस महत्वपूर्ण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए नगर निगम ने विशेष कार्ययोजना तैयार की है। सफाई अभियान के लिए अनुबंधित दो एजेंसियों मेसर्स श्री दास एंड कंपनी तथा मेसर्स गीता इंटरप्राइजेज को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों एजेंसियों की दो-दो टीमों को अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात किया गया है। कुल चार टीमें प्रतिदिन विभिन्न जोनों में पहुंचकर चेंबरों की सफाई और निरीक्षण का कार्य कर रही हैं।

निगम अधिकारियों ने बताया कि सफाई कार्य के दौरान केवल चेंबरों की सफाई ही नहीं की जा रही, बल्कि यह भी जांचा जा रहा है कि कहीं लाइन क्षतिग्रस्त तो नहीं है, किसी स्थान पर अवैध कनेक्शन तो नहीं जोड़े गए हैं और कहीं पानी के प्रवाह में कोई तकनीकी बाधा तो नहीं है। जहां भी ऐसी समस्याएं सामने आएंगी, वहां तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शहर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेजी से हुए शहरी विस्तार के कारण जल निकासी व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा है। ऐसे में स्टार्म वाटर नेटवर्क का नियमित रखरखाव अत्यंत आवश्यक हो गया है। नगर निगम का मानना है कि यदि मानसून से पहले पूरी व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाए तो भारी बारिश के दौरान भी अधिकांश क्षेत्रों में पानी का जमाव रोका जा सकता है।

नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि लोग नालियों, चेंबरों और सड़कों पर कचरा, प्लास्टिक, निर्माण सामग्री या अन्य अपशिष्ट न फेंकें। अक्सर देखा जाता है कि प्लास्टिक और ठोस कचरा स्टार्म वाटर लाइनों में पहुंचकर उन्हें चोक कर देता है, जिससे जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होती है। यदि नागरिक भी जिम्मेदारी निभाएं तो शहर को जलभराव की समस्या से काफी हद तक बचाया जा सकता है।n निगम आयुक्त के निर्देश पर चलाया जा रहा यह अभियान शहर के प्रमुख मार्गों, व्यावसायिक क्षेत्रों, आवासीय कॉलोनियों और संवेदनशील जलभराव वाले स्थानों पर विशेष फोकस के साथ संचालित किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में पूर्व वर्षों में पानी भरने की शिकायतें अधिक मिली थीं। वहां अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर विशेष सफाई दल भी तैनात किए जाएंगे।

रणजीत टाइम्स

महाकाल भस्म आरती के नाम पर ठगी!

श्रद्धालु से 4250 ऐंठे, ऑनलाइन जालसाजों का नया खेल

उज्जैन विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में शामिल होने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं को अब साइबर ठग अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामले में एक श्रद्धालु से भस्म आरती में प्रवेश दिलाने और वीआईपी व्यवस्था का झांसा देकर 4250 की ठगी कर ली गई। पीड़ित श्रद्धालु ने बताया कि उसे सोशल मीडिया और इंटरनेट पर उपलब्ध एक नंबर के माध्यम से संपर्क मिला। सामने वाले व्यक्ति ने खुद को मंदिर व्यवस्था से जुड़ा बताते हुए भस्म आरती की बुकिंग कराने का दावा किया। इसके बाद ऑनलाइन भुगतान करवाकर संपर्क तोड़ दिया।

आस्था को बना रहे हथियार

साइबर अपराधी अब धार्मिक स्थलों और प्रसिद्ध मंदिरों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन और भस्म आरती के लिए पहुंचते हैं, जिसका फायदा उठाकर ठग फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया पेज और मोबाइल नंबरों के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं।

मंदिर प्रशासन की अपील

मंदिर प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि भस्म आरती, दर्शन, वीआईपी पास या किसी भी प्रकार की बुकिंग केवल आधिकारिक माध्यमों से ही कराएं। किसी अनजान व्यक्ति, एजेंट या सोशल मीडिया पर मिले नंबर पर पैसे ट्रांसफर न करें।

बढ़ रहे साइबर अपराध

विशेषज्ञों का कहना है कि धार्मिक पर्यटन बढ़ने के साथ-साथ इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कई मामलों में श्रद्धालु जल्दबाजी या जानकारी के अभाव में ठगी का शिकार हो जाते हैं।

कैसे बचें?-केवल आधिकारिक पोर्टल से ही बुकिंग करें। सोशल मीडिया पर दिखने वाले विज्ञापनों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।

किसी निजी खाते में पैसे ट्रांसफर करने से पहले पूरी जांच करें। ठगी होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं। बड़ा सवाल-जब आस्था भी साइबर अपराधियों के निशाने पर है, तब क्या श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए और सख्त अभियान चलाने की जरूरत नहीं है? महाकाल के नाम पर हुई यह ठगी एक बार फिर चेतावनी देती है कि ऑनलाइन सुविधा के साथ सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है।

"पुलिस वाले ही वसूली करने लगें तो आम आदमी कहां जाएगा?" सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, तीन पुलिसकर्मियों की जमानत रद्द

देश की सर्वोच्च अदालत ने जौहरी से कथित जबरन वसूली के मामले में तीन पुलिसकर्मियों को मिली अग्रिम जमानत रद्द करते हुए पुलिस तंत्र पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि जब कानून लागू करने वाले ही जबरन वसूली करने वाले बन जाएं, तो आम नागरिकों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की वर्दी जनता की सुरक्षा और कानून के पालन के लिए होती है, न कि उसका दुरुपयोग कर लोगों को डराने या अवैध वसूली करने के लिए। अदालत ने टिप्पणी की कि "यदि पुलिसकर्मी ही वसूली करने लगें, तो आम आदमी न्याय और सुरक्षा के लिए आखिर किसके पास जाएगा?" मामला एक जौहरी से कथित रूप से धमकाकर पैसे वसूलने के आरोपों से जुड़ा है। आरोप है कि संबंधित पुलिसकर्मियों ने अपने पद और अधिकार का इस्तेमाल कर दबाव बनाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत को अनुचित मानते हुए उसे रद्द कर दिया।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून के रक्षक यदि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, तो ऐसे मामलों को सामान्य अपराध की तरह नहीं देखा जा सकता। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं जनता के विश्वास को कमजोर करती हैं और कानून व्यवस्था की साख को नुकसान पहुंचाती हैं।

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को पुलिस जवाबदेही और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एककड़ा संदेश माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत ने साफ कर दिया है कि वर्दी की आड़ में होने वाले कथित भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।

वृद्धाश्रम में भीषण आग से मची चीख-पुकार, 11 बुजुर्गों की मौत व सात बुरी तरह झुलसे

श्रीलंका में एक वृद्धाश्रम में आग लगने से कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और सात अन्य बुजुर्ग झुलस गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे कलुतारा जिले के

अंगुरुवाटोटा स्थित मावपिया सेवाना वृद्धाश्रम में आग लग गई। यह स्थान कोलंबो से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है। पुलिस ने बताया कि परिसर में 10 लोग मृत पाए गए जबकि एक अन्य बुजुर्ग ने होराना बेस अस्पताल में भर्ती होने के बाद दम तोड़ दिया।

पुलिस के मुताबिक, कुल 51 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया जबकि सात घायल अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने बताया कि निवासियों और पुलिस की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शुरुआती खबरों में सामने आया कि घटना के दौरान एक गैस सिलेंडर फट गया, जिससे आग तेजी से फैल गई। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का सटीक कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। 'न्यूजफर्स्ट डॉट एलके' समाचार पोर्टल के अनुसार, बचाए गए लोगों को अस्थायी रूप से पास के एक स्कूल में ठहराया गया है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जा रही है।

विप्रो में भी TCS जैसा कांड! पूर्व कर्मचारी बोली- हिंदू महिलाओं का हो रहा उत्पीड़न, आवाज उठाने पर नौकरी से निकाला

पुणे के हिंजवडी स्थित विप्रो में कार्यरत एक पूर्व महिला कर्मचारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी पर उत्पीड़न और बात न मानने पर नौकरी से निकालने का आरोप लगाया हैं। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

"प्रकृति है तो जीवन है"

विश्व पर्यावरण दिवस शुभकामनायें

पर्यावरण दिवस पर विशेष लेख
राजेश धाकड़ की कलम से

5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और प्रकृति को बचाने के लिए प्रेरित करना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद की गई थी। तब से हर साल यह दिवस एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है।

वर्ष 2026 की थीम है -"Land Restoration, Desertification and Drought Resilience" अर्थात-भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोध।

आज पर्यावरण कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, प्लास्टिक कचरा, जल संकट और जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। लगातार बढ़ती गर्मी और मौसम में हो रहे बदलाव इसके स्पष्ट संकेत हैं। शहरों में तापमान हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है, वहीं कई क्षेत्रों में बारिश का पैटर्न भी बदलता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि धरती को बचाने का संकल्प लेने का अवसर है।

हम क्या कर सकते हैं?

पेड़ लगाएं-हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ न केवल ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि तापमान नियंत्रित रखने में भी मदद करते हैं।

प्लास्टिक को कहें ना-सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करना बेहद जरूरी है। बाजार जाते समय कपड़े या जूट के थैले का इस्तेमाल करना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।

पानी बचाएं-पानी की बचत आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है। बेवजह पानी बहाने से बचना चाहिए और वर्षा जल संचयन को अपनाना चाहिए।

कचरे को अलग करें-घर में गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखना स्वच्छता और रिसाइक्लिंग में मदद करता है।

बिजली बचाएं-LED बल्ब, सोलर ऊर्जा और जरूरत न होने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद रखने जैसी आदतें भी पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाती हैं। देश के कई शहर स्वच्छता और हरियाली के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। लोगों की भागीदारी से ही स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का निर्माण संभव है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह संदेश देता है कि यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। आइए इस अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे, पेड़ लगाएंगे और पर्यावरण को बचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। पर्यावरण दिवस पर हम सभी संकल्प लेते हैं एक पौधा लगाए पर्यावरण बचाएं

"प्रकृति है तो जीवन है,
पर्यावरण है तो भविष्य है।"

आबकारी विभाग पेटलावद द्वारा ग्राम तलावपाड़ा, रायपुरिया से अवैध शराब जप्त की

सलीम हूसैन

झाबुआ, 04 जून जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट एवं उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संभाग इंदौर इंदरसिंह जामोद द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ बसंती भूरिया के निर्देशन में कार्यवाही की गई। 04 जून को मुखबिर की सूचना पर ग्राम रायपुरिया में मुखबिर द्वारा बताये स्थान में पहुंच कर मकान की विधिवत तलाशी लेने पर विदेशी मदिरा लेमाउण्ट कैन बीयर 12 पेटी, देशी मदिरा प्लेन 01 पेटी कुल-13 पेटी (कुल-153 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मौके से फरार आरोपी अमरसिंह पिता गलिया डामोर, निवासी तलावपाड़ा रायपुरिया के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि 44120/- रूपये होना पाया। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

हृदय संबंधी समस्यायों के समाधान में सहायक है सहजयोग

आज का युवा आधुनिकता, प्रतिस्पर्धा और भागदौड़ भरे जीवन के बीच बाहरी सफलता तो प्राप्त कर रहा है, लेकिन भीतर से तनाव, चिंता और असंतुलन का शिकार होता जा रहा है। यही मानसिक अशांति धीरे-धीरे शरीर पर प्रभाव डालती है और कम उम्र में ही हृदय संबंधी समस्याओं को जन्म देती है। बढ़ता रक्तचाप, अनियमित धड़कन, बेचैनी और तनाव आज युवाओं के जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं।

हृदय और मन का गहरा संबंध

आध्यात्मिक दृष्टि से हृदय केवल शरीर का अंग नहीं, बल्कि भावनाओं, प्रेम, करुणा और आत्मिक चेतना का केंद्र माना गया है। जब मन अशांत होता है, जीवन में भय, क्रोध, असुरक्षा और तनाव बढ़ते हैं, तब उसका सीधा प्रभाव हृदय पर पड़ता है। आधुनिक जीवनशैली ने मनुष्य को बाहरी सुखों के पीछे तो दौड़ाया, परंतु भीतर की शांति उससे दूर होती चली गई। सहजयोग का मूल संदेश है कि वास्तविक स्वास्थ्य तभी संभव है, जब मन, शरीर और आत्मा में संतुलन स्थापित हो। श्री माताजी निर्मला देवी जी द्वारा स्थापित सहजयोग व्यक्ति के भीतर स्थित सूक्ष्म ऊर्जा शक्ति कुंडलिनी — के जागरण पर आधारित है। सहजयोग में ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शांति, आनंद और चेतना को अनुभव करता है। जब मन शांत होता है, तब हृदय पर तनाव का बोझ कम होने लगता है। सहजयोग के अभ्यास से

व्यक्ति भीतर से हल्का, संतुलित और आनंदित महसूस करता है।

हृदय स्वास्थ्य में सहजयोग की आध्यात्मिक भूमिका

1. मानसिक तनाव से मुक्ति

सहजयोग ध्यान मन को वर्तमान में स्थिर करता है। इससे भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ कम होता है। मन शांत होने पर हृदय भी सहज रूप से स्वस्थ रहने लगता है।

2. सकारात्मक भावनाओं का विकास

प्रेम, करुणा, क्षमा और संतोष जैसे गुण हृदय को हल्का बनाते हैं। सहजयोग इन भावनाओं को जागृत करने में सहायक माना जाता है।

3. जीवनशैली में संतुलन

जो व्यक्ति नियमित ध्यान करता है, वह धीरे-धीरे संयमित जीवन और सकारात्मक विचारों की ओर आकर्षित होने लगता है। यही संतुलन हृदय को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

4. आत्मिक आनंद की प्राप्ति

सहजयोग का उद्देश्य केवल रोगों से राहत नहीं, बल्कि आत्मिक आनंद की अनुभूति भी है। जब व्यक्ति भीतर से प्रसन्न होता है, तब उसका प्रभाव शरीर और हृदय दोनों पर दिखाई देता है तथा इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक व आध्यात्मिक रूप से सक्षम व संतुलित हो जाता है।

चिकित्सा और अध्यात्म का संतुलन

यह आवश्यक है कि हृदय संबंधी किसी भी समस्या में चिकित्सकीय सलाह अवश्य ली जाए। सहजयोग आधुनिक चिकित्सा का विकल्प नहीं, बल्कि एक सहायक आध्यात्मिक पद्धति है जो ऋषियों व मनीषियों द्वारा स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, यह व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। विश्वभर में लाखों साधकों ने सहजयोग में सूक्ष्म चक्रों, नाड़ियों तथा कुंडलिनी शक्ति के संतुलन द्वारा अनेक शारीरिक समस्याओं से निजात पाई है। यूं तो मनुष्य ने विज्ञान और तकनीक में बहुत प्रगति की है।

अफसर पहुंचे आदिवासियों की चौखट पर: पुनावली में रात्रि चौपाल, 27 समस्याएं मौके पर निपटीं, हाथों-हाथ बंटे प्रमाणपत्र

अतुल जैन

(SDM ममता शाक्य बोलीं- दिन में मजदूरी, रात में सुनवाई; अब हर सप्ताह पंचायतों में लगेगी चौपाल)
(ग्रामीणों ने कहा- 'पहली बार साहब जमीन पर बैठे, काम भी किया')

पिछोर। 'साहब लोग पहली बार हमारे गांव आए, खटिया नहीं मिली तो जमीन पर ही बैठ गए और पल भर में कागज बनाकर दे दिए...' यह कहना है ग्राम पुनावली के आदिवासी ग्रामीणों का। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर बुधवार रात पिछोर जनपद की ग्राम पंचायत नावली के मजरा पुनावली में प्रशासन ने अनूठी 'रात्रि चौपाल' लगाई। SDM राजस्व ममता शाक्य के नेतृत्व में राजस्व से लेकर पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य व पशुपालन विभाग के अफसर ग्रामीणों के बीच पहुंचे और देर रात तक 27 समस्याओं का मौके पर ही पटाक्षेप कर दिया।

(चटाई पर बैठा पूरा प्रशासन)

रात करीब 8 बजे शुरू हुई चौपाल में अतिरिक्त जिला CEO एन.एस. नरवरिया, तहसीलदार शिवशंकर सिंह गुर्जर, नायब तहसीलदार शुभम गर्ग, CDPO अरविंद तिवारी, BEO विनोद गुप्ता, BRCC सुरेश गुप्ता, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. हेमंत ओझा समेत पटवारी, सचिव, रोजगार सहायक व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं मौजूद रहीं। अफसरों ने टेंट-कुर्सी की जगह ग्रामीणों के साथ चटाई पर बैठकर एक-एक फरियाद सुनी।

(कौन-कौन से काम हुए चुटकियों में)

SDM ममता शाक्य ने बताया कि चौपाल का मकसद दिन में खेत-खलिहान व मजदूरी पर गए आदिवासी परिवारों से रात में सीधा संवाद करना है। ग्रामीणों से फौती नामांतरण, राशन वितरण, वृद्धावस्था पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, पशु KCC, अपार ID, प्रधानमंत्री आवास की रुकी किस्त व राशन कार्ड में नाम जोड़ने संबंधी समस्याएं सामने आईं। मौके पर ही 27 प्रकरणों का निराकरण कर हितग्राहियों को जाति प्रमाणपत्र, जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र, वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति पत्र, फौती नामांतरण व अन्य योजनाओं के प्रमाणपत्र सौंप दिए गए।

('फार्मर रजिस्ट्री जरूर बनवाएं' : SDM)

SDM शाक्य ने ग्रामीणों से अपील की कि पटवारी अगले सप्ताह गांव में कैंप लगाएंगे। सभी किसान फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से बनवा लें। जिनका PM किसान सम्मान निधि में पंजीयन नहीं हुआ है, वे आधार, खसरा व बैंक पासबुक लेकर पंजीयन करा लें, ताकि 6 हजार रुपये सालाना की किस्त न रुके।

(हर बुधवार को नई पंचायत में चौपाल)

अतिरिक्त जिला CEO एन.एस. नरवरिया ने कहा, "मुख्यमंत्री की मंशा है कि सरकार गांव के दरवाजे तक पहुंचे। अब हर सप्ताह बुधवार रात को पिछोर जनपद की किसी न किसी पंचायत में रात्रि चौपाल लगेगी। इससे योजनाओं का फीडबैक भी मिलेगा और लंबित काम भी मौके पर निपटेंगे।"

(ग्रामीण बोले- साहब ने दिल जीत लिया)

70 वर्षीय बुजुर्ग कल्लू आदिवासी की आंखें भर आईं। बोले, "पेंशन के लिए 3 साल से भटक रहा था। मैडम ने यहीं कागज बनाकर दे दिया।" वहीं सुखिया बाई ने कहा, "पति के मरने के बाद फौती नामांतरण नहीं हुआ था। आज बेटे के नाम खेत हो गया। साहब लोगों ने हम गरीबों का मान बढ़ा दिया।"

(अफसरों की पाठशाला)

चौपाल में BEO विनोद गुप्ता ने स्कूल न जाने वाले बच्चों की सूची बनाई, CDPO अरविंद तिवारी ने पोषण आहार व लाड़ली बहना के फॉर्म भरवाए, डॉ. हेमंत ओझा ने पशुओं का टीकाकरण शेड्यूल बताया। रात 11 बजे तक चली चौपाल में ग्रामीणों को योजनाओं की पूरी जानकारी दी गई।

सार्वजनिक हनुमान मंदिर बचाने हेतु सर्व हिन्दू समाज का आंदोलन, मीडिया से न्याय की अपील

राजेश धाकड़

इंदौर। पंचशील कॉलोनी मूसाखेड़ी गली नंबर 4 स्थित सार्वजनिक हनुमान मंदिर को बचाने के लिए सर्व हिन्दू समाज द्वारा आंदोलन किया गया तथा मीडिया के माध्यम से न्याय की अपील की गई। आंदोलन में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एवं समाजजन उपस्थित रहे। हिन्दू समाज के प्रतिनिधियों में रजत पंडित, दयाल सोनकर, अक्षय गेहलोत, जितेन जालौरिया, संजय सिलावट सहित समस्त मोहल्लेवासी मौजूद रहे। वहीं बलाई समाज की ओर से वरिष्ठ कांता चौहान, पंकज चौहान, पोरवाल, सोलंकी एवं परमार समाजजन ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।समाजजनों ने कहा कि सार्वजनिक हनुमान मंदिर आस्था का केंद्र है और इसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। आंदोलनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि मंदिर को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे तथा आमजन की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाए। मौजूद लोगों ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से निष्पक्ष कार्रवाई और न्याय की मांग की।

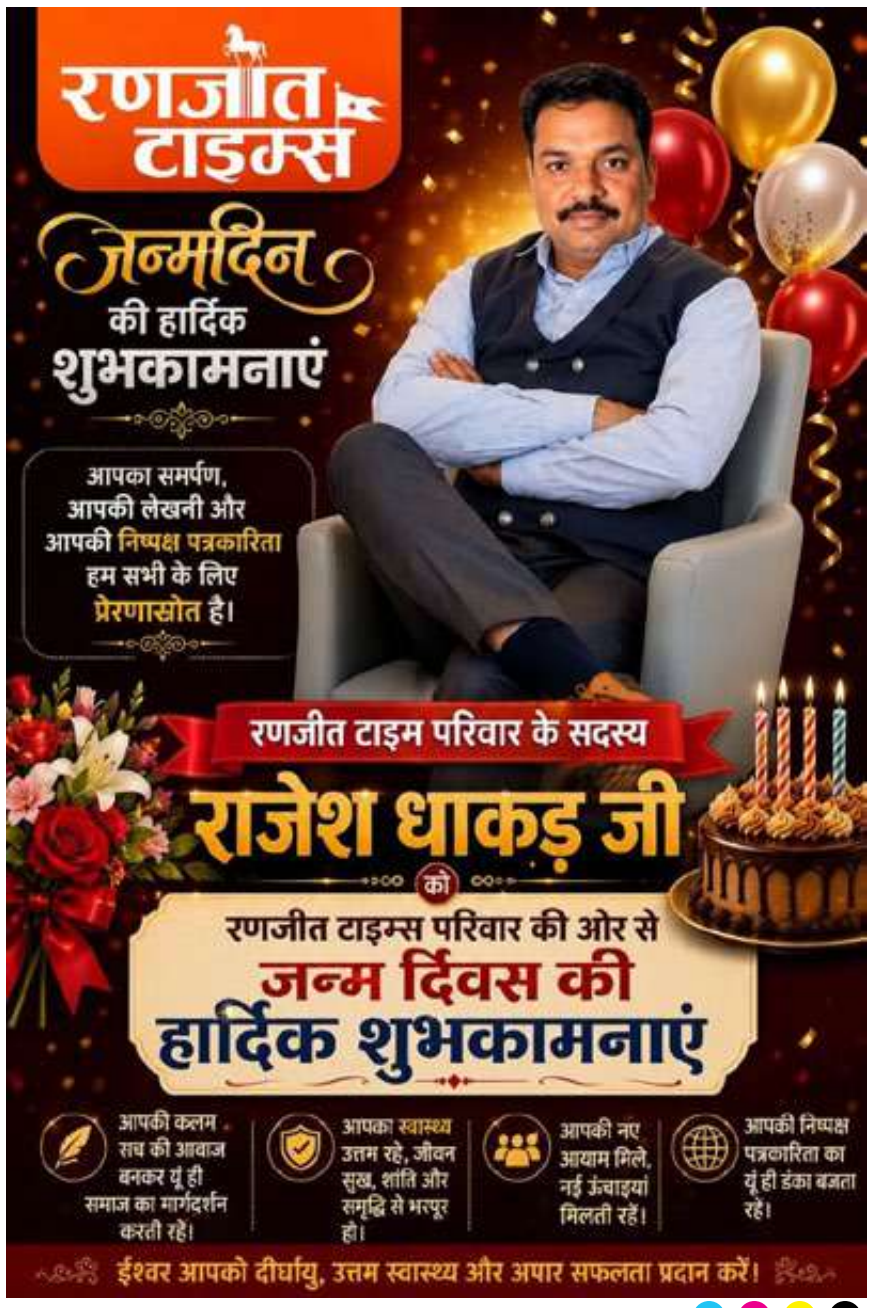

जिस चीज के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है बेंगलुरु

उसे सुधारने में जुटे शिवकुमार; CM बनते ही लिया बड़ा फैसला

कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री D. K. Shivakumar ने पद संभालते ही उस समस्या पर फोकस किया है, जिसके लिए Bengaluru की पहचान अक्सर ट्रैफिक जाम, टूटी सड़कों और गड्ढों वाले शहर के रूप में होती रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठकों में शिवकुमार सरकार ने बेंगलुरु की सड़कों के सुधार के लिए 2,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। यह राशि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी और बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत सड़क बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी।

सड़कों और ट्रैफिक पर पहला फोकस-आईटी हब होने के बावजूद बेंगलुरु वर्षों से ट्रैफिक जाम और खराब सड़कों की समस्या से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने संकेत दिए हैं कि उनकी सरकार की प्राथमिकता राजधानी की आधारभूत सुविधाओं को दुरुस्त करना होगी। पहली कैबिनेट बैठक में ही सड़कों के डामरीकरण और मरम्मत को शीर्ष एजेंडे में रखा गया।

सिर्फ सड़कें नहीं, ये बड़े फैसले भी-सरकार ने छात्रों के लिए राज्यभर में फ्री बस पास योजना की घोषणा की है, जिससे स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही निजी रोजगार विनिमय (Private Employment Exchange) और युवा संगठनों के गठन की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा बेंगलुरु में संपत्ति मालिकों को राहत देने के लिए वन-टाइम सेटलमेंट योजना और भवनों के दस्तावेजीकरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं।

राजनीतिक संदेश भी साफ-मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद शिवकुमार का पहला बड़ा प्रशासनिक संदेश यही माना जा रहा है कि उनकी सरकार बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर संकट को प्राथमिकता देगी। राजधानी की सड़कें, ट्रैफिक और शहरी सुविधाएं आगामी वर्षों में सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होंगी। बेंगलुरु को अक्सर देश की "सिलिकॉन वैली" कहा जाता है, लेकिन अब शिवकुमार सरकार के सामने चुनौती यह है कि शहर को तकनीकी राजधानी के साथ-साथ बेहतर सड़कों और सुगम यातायात वाला महानगर भी बनाया जाए।

चाचा-भतीजे की सियासी जंग से लेकर आंतरिक कलह तक...

नई दिल्ली। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन पिछला एक दशक राजनीतिक उठापटक और बड़े दलों के विभाजन का गवाह रहा है। देश के चार बड़े राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में पांच ऐसे प्रमुख राजनीतिक दल रहे हैं। जिन्हें अपनों की ही बगावत और आंतरिक कलह का सामना करना पड़ा। इन विवादों के बाद न सिर्फ पार्टियों के सिंबल बदले, बल्कि राज्यों के सियासी समीकरण भी पूरी तरह बदल गए।

शिवसेना और एनसीपी में अपनों ने ही की बगावत

महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में दो सबसे बड़े सियासी उलटफेर देखने को मिले। साल 2022 में शिवसेना के भीतर एकनाथ शिंदे ने तत्कालीन नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी। इस अंदरूनी कलह के बाद मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा, जहां से एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना नाम और आधिकारिक चुनाव चिह्न तीर-कमान मिला।

बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की तैयारी, 'वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय' प्रस्ताव को मिली मंजूरी

नाम बदलकर 'वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय' किए जाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद (Executive Council) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, यह निर्णय परमार वंश के महान शासक राजा भोज की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है। भोपाल का प्राचीन नाम भोजपाल माना जाता है, जो राजा भोज से जुड़ा हुआ है। इसी ऐतिहासिक पहचान को ध्यान में रखते हुए नए नाम का प्रस्ताव तैयार किया गया। स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को लेकर विश्वविद्यालय के भीतर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। कार्यपरिषद की मंजूरी के बाद अब इस प्रक्रिया का अगला चरण राज्य सरकार और कुलाधिपति (राज्यपाल) की स्वीकृति से जुड़ा होगा। नाम परिवर्तन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी बहस शुरू हो गई है। समर्थकों का कहना है कि इससे क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान और राजा भोज की विरासत को सम्मान मिलेगा, जबकि कुछ लोग विश्वविद्यालय की मौजूदा पहचान और इतिहास को बनाए रखने की बात कर रहे हैं। यदि राज्यपाल की मंजूरी मिल जाती है तो आने वाले समय में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय आधिकारिक रूप से 'वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय' के नाम से जाना जाएगा। यह निर्णय मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के नाम पर संस्थानों के नामकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बागी, विद्रोह और मेयर का इस्तीफा...

कोलकाता। बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथों करारी हार के कुछ दिनों बाद, तृणमूल कांग्रेस अपने विधायी रैंकों में विद्रोह से जूझ रही है।इस बीच बिधाननगर की मेयर कृष्णा चक्रवर्ती ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने निगमायुक्त को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। बंगाल की सत्ता से उखड़ने के बाद तृणमूल कांग्रेस को यह एक और झटका है। मालूम हो कि बिधाननगर नगर निगम में वर्तमान में तृणमूल का बोर्ड है।इस्तीफे के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा- मैंने व्यक्तिगत कारणों से यह निर्णय लिया है। मुझे अपने लिए कुछ समय चाहिए।

मैं पार्षद के रूप में काम करती रहूंगी। बिधाननगर के लोगों से मुझे जो प्यार मिला है, उसके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी।यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी पार्टी या किसी व्यक्ति से कोई नाराजगी है तो उन्होंने इससे इनकार किया। कृष्णा को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबियों में गिना जाता है। वह पिछले 16 वर्षों से बिधाननगर नगर निगम से जुड़ी हैं। इस दौरान उन्होंने बोरो चेयरमैन और मेयर जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली।

सिरपुर तालाब की जीवनदायिनी चैनल पर चला बुलडोजर

इंदौर। शहर के पर्यावरण और जल संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण जलस्रोत सिरपुर तालाब को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तालाब की मुख्य जल आपूर्ति चैनल पर किए गए अवैध कब्जों को हटाना शुरू कर दिया है। वर्षों पुरानी इस चैनल को बंद कर वहां सड़क बना दी गई थी और आसपास की कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने की तैयारियां भी चल रही थीं। मामले की जानकारी सामने आने के बाद नगर निगम का रिमूवल अमला भारी मशीनरी और अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचा तथा जेसीबी मशीनों की मदद से चैनल पर बनाई गई सड़क को खोदकर हटाने की कार्रवाई की गई।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह पूरा मामला शहर के कैट क्षेत्र के पीछे स्थित सिरपुर गांव के आसपास का है, जहां सिरपुर तालाब तक पानी पहुंचाने वाली एक महत्वपूर्ण और प्राकृतिक जल निकासी चैनल कई वर्षों से मौजूद थी। यह चैनल बारिश के पानी के प्रवाह और तालाब के जलस्तर को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में जमीन की बढ़ती कीमतों और अवैध कॉलोनियों के विस्तार के कारण कुछ लोगों ने इस चैनल पर धीरे-धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया था।

इजराइल-लेबनान में फिर सीजफायर पर सहमति, दक्षिणी लेबनान में बनेंगे सुरक्षा क्षेत्र

हिज्बुल्लाह को हटाने की योजना, लेबनानी सेना संभालेगी नियंत्रण

बेरूत। मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी तनाव के बीच इजराइल और लेबनान ने अमेरिका की मध्यस्थता में एक बार फिर युद्धविराम (सीजफायर) लागू करने पर सहमति जताई है। समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान में विशेष सुरक्षा क्षेत्र (सिक्योरिटी जोन) बनाए जाएंगे, जहां हिज्बुल्लाह की सैन्य मौजूदगी नहीं रहेगी। समझौते के अनुसार इन क्षेत्रों की सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण की जिम्मेदारी लेबनानी सेना को सौंपी जाएगी। इसका उद्देश्य सीमा क्षेत्र में तनाव कम करना और दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव की संभावना को घटाना बताया जा रहा है।

हिज्बुल्लाह की भूमिका पर फोकस

इजराइल लंबे समय से दक्षिणी लेबनान में हिज्बुल्लाह की गतिविधियों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताता रहा है। नई व्यवस्था के तहत ऐसे इलाकों को हिज्बुल्लाह की सैन्य गतिविधियों से मुक्त रखने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि राजनीतिक और सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जमीन पर इस समझौते को

लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्र में वर्षों से हिज्बुल्लाह का प्रभाव बना हुआ है।

सीजफायर के बावजूद तनाव बरकरार

युद्धविराम पर सहमति के बावजूद दोनों पक्षों के बीच अविश्वास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हाल के दिनों में इजराइली सैन्य कार्रवाइयों और हिज्बुल्लाह से जुड़े घटनाक्रमों के कारण क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि यदि दोनों पक्ष समझौते की शर्तों का पालन करते हैं तो यह मध्य पूर्व में स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। लेकिन किसी भी उल्लंघन की स्थिति में हालात फिर से बिगड़ सकते हैं।

अमेरिका की अहम भूमिका

इस समझौते में अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। वॉशिंगटन का मानना है कि सीमा क्षेत्र में स्थिरता आने से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका कम होगी और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि क्या यह नया सीजफायर वास्तव में शांति का रास्ता खोलेगा या फिर यह भी पिछले समझौतों की तरह सीमित अवधि तक ही टिक पाएगा।

सुक्खू सरकार के एंट्री टैक्स के खिलाफ निहंग सिखों का अनोखा विरोध, हिमाचल की गाड़ियों से वसूला 'खालसा टैक्स'

Himachal Pradesh में लागू प्रवेश कर (Entry Tax) को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसी बीच निहंग सिख संगठनों ने सरकार के खिलाफ अनोखे अंदाज में मोर्चा खोल दिया है। किरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर निहंग सिंहों ने 'खालसा टैक्स' अभियान चलाकर हिमाचल सरकार के फैसले का विरोध दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार, Baba Achar Singh Mahakal के नेतृत्व में गड़ा मोरा टोल प्लाजा पर यह प्रतीकात्मक अभियान चलाया गया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश नंबर की गाड़ियों को रोककर चालकों से स्वैच्छिक चंदे के रूप में राशि ली गई, जिसे निहंग संगठनों ने 'खालसा टैक्स' का नाम दिया।

निहंग नेताओं का कहना है कि हिमाचल सरकार द्वारा लगाए गए प्रवेश कर से पंजाब और अन्य राज्यों से आने-जाने वाले लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उनका आरोप है कि सरकार का यह फैसला आम जनता और व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित करेगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान निहंग संगठनों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार की जबरन वसूली नहीं, बल्कि सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करना है।

उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरी तरह प्रतीकात्मक है और इसका मकसद मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu के नेतृत्व वाली सरकार पर प्रवेश कर वापस लेने का दबाव बनाना है। इस घटनाक्रम ने हिमाचल और पंजाब की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। विपक्षी दल भी एंट्री टैक्स के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, जबकि सरकार का तर्क है कि यह कर राज्य के राजस्व और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक है। अब देखना होगा कि बढ़ते विरोध और राजनीतिक दबाव के बीच सुक्खू सरकार इस फैसले पर कायम रहती है या प्रवेश कर को लेकर कोई नई घोषणा करती है।

ट्रंप को अपनी ही पार्टी ने दिया झटका!

ईरान पर सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए संसद में प्रस्ताव पास

रिपब्लिकन सांसदों ने भी नहीं दिया पूरा साथ, युद्ध के मुद्दे पर व्हाइट हाउस पर बढ़ा दबाव

वॉशिंगटन। ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी संसद ने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई संबंधी शक्तियों को सीमित करना है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस प्रस्ताव को ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों का भी समर्थन मिला। प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी लंबे सैन्य अभियान या युद्ध जैसी कार्रवाई को कांग्रेस की मंजूरी के बिना आगे नहीं बढ़ा सकते। सांसदों का तर्क है कि संविधान के अनुसार युद्ध संबंधी अंतिम अधिकार कांग्रेस के पास होना चाहिए और किसी भी बड़े सैन्य अभियान से पहले संसद की स्वीकृति अनिवार्य है।

ट्रंप प्रशासन पर बढ़ा दबाव

ईरान को लेकर अमेरिका में लंबे समय से राजनीतिक बहस चल रही है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पहले से ही ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति पर सवाल उठाती रही है, लेकिन अब कुछ रिपब्लिकन सांसदों के भी अलग रुख अपनाने से व्हाइट हाउस की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल विदेश नीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति और कांग्रेस के अधिकारों की लड़ाई भी बनता जा रहा है। संसद का यह कदम ट्रंप प्रशासन के लिए एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश माना जा रहा है।

युद्ध नहीं, संसद की मंजूरी जरूरी

कांग्रेस के कई सदस्यों का कहना है कि अमेरिका को किसी नए युद्ध में झोंकने से पहले जनता के प्रतिनिधियों की सहमति आवश्यक है। उनका तर्क है कि पिछले कई दशकों में अमेरिका लंबे सैन्य अभियानों का भारी आर्थिक और

मानवीय मूल्य चुका चुका है।

चुनावी राजनीति पर भी असर

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का मुद्दा आगामी अमेरिकी राजनीति में भी बड़ा विषय बन सकता है। यदि राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ता है तो इसका असर ट्रंप की राजनीतिक रणनीति और जनसमर्थन पर भी पड़ सकता है।

दुनिया की नजर वॉशिंगटन पर

ईरान और अमेरिका के संबंध पहले से तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी संसद का यह फैसला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप प्रशासन इस बढ़ते राजनीतिक और कानूनी दबाव का सामना किस तरह करता है।

संदेश साफ है—ईरान पर सैन्य कार्रवाई के मुद्दे पर अब केवल व्हाइट हाउस की नहीं, बल्कि अमेरिकी संसद की भी निर्णायक भूमिका होगी।

बीके हरिप्रसाद बने कर्नाटक कांग्रेस के नए अध्यक्ष

डीके शिवकुमार की जगह संभालेंगे संगठन की कमान

कांग्रेस हाईकमान ने वरिष्ठ नेता B. K. Hariprasad को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है।

D. K. Shivakumar की जगह लेंगे, जो हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब कांग्रेस ने कर्नाटक में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन किया है। डीके शिवकुमार ने 3 जून 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद संगठन और सरकार को अलग-अलग नेतृत्व देने की रणनीति के तहत नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश पूरी की गई।

कौन हैं बीके हरिप्रसाद?

B. K. Hariprasad कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। वे लंबे समय तक पार्टी संगठन में सक्रिय रहे हैं और राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। कर्नाटक की राजनीति में उन्हें संगठनात्मक कौशल और रणनीतिक सोच के लिए जाना जाता है। पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों के बीच संतुलन बनाने वाले नेता के रूप में उनकी पहचान रही है।

कांग्रेस का बड़ा संगठनात्मक संदेश

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी ने संगठन और सरकार के बीच स्पष्ट जिम्मेदारियां तय करने का फैसला किया है। हरिप्रसाद की नियुक्ति को 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी और संगठन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राजनीतिक मायने

मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिवकुमार सरकार का नेतृत्व करेंगे

बीके हरिप्रसाद संगठन की कमान संभालेंगे। कांग्रेस नेतृत्व राज्य में सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।

आगामी चुनावों को देखते हुए

बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी हरिप्रसाद के कंधों पर होगी। कर्नाटक में कांग्रेस के इस नेतृत्व परिवर्तन को पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन और भविष्य की चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हैदराबाद में ओवैसी ने तेज किया SIR अभियान, मतदाताओं से बोले- "नाम कटने न दें, दस्तावेज तैयार रखें"

ने हैदराबाद में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें और आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करें, ताकि किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची से न हटे। ओवैसी ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है और हर नागरिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज रहे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रतिनिधियों से भी लोगों को जागरूक करने तथा दस्तावेजी प्रक्रिया में सहायता करने का आह्वान किया। हैदराबाद में आयोजित बैठकों और जनसंपर्क कार्यक्रमों के दौरान ओवैसी ने लोगों से मतदाता सूची के सत्यापन अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता को कोई त्रुटि दिखाई देती है तो उसे तत्काल संबंधित चुनाव अधिकारियों के समक्ष सुधार के लिए आवेदन करना चाहिए।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार

मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विभिन्न दलों ने अपनी-अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। ऐसे में ओवैसी का यह अभियान हैदराबाद की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां AIMIM का मजबूत जनाधार माना जाता है। में आने वाले चुनावी समीकरणों को देखते हुए इस अभियान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

2027 का शंखनाद!

बीजेपी से पहले चुनावी मैदान में उतरे राहुल फोन से अल्मोड़ा रैली को किया संबोधित

अंकिता भंडारी हत्याकांड को बनाया मुद्दा, कांग्रेस ने उत्तराखंड में चुनावी बिगुल फूंका

उत्तराखंड की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। बीजेपी के चुनावी अभियान को पूरी तरह गति मिलने से पहले ही कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खराब मौसम के कारण अल्मोड़ा नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने फोन के जरिए विशाल जनसभा को संबोधित कर 2027 के चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। कांग्रेस ने इस रैली के जरिए अंकिता भंडारी हत्याकांड को फिर से राजनीतिक केंद्र में ला दिया। पार्टी का आरोप है कि प्रदेश सरकार अब तक इस मामले में कई सवालों का जवाब देने में असफल रही है। राहुल गांधी ने भी अपने संबोधन में न्याय, जवाबदेही और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठाया।

बीजेपी पर सीधा हमला

राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि सरकार जनता के मूल सवालों से बच रही है। कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि 2027 का चुनाव रोजगार, महिला सुरक्षा और जवाबदेही के मुद्दों पर लड़ा जाएगा।

अंकिता भंडारी केस बना चुनावी हथियार

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में अंकिता भंडारी हत्याकांड को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। यही वजह है कि अल्मोड़ा की रैली को पार्टी के लिए प्रतीकात्मक और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था।

उत्तराखंड में शुरू हुई सियासी जंग

राहुल गांधी भले ही मौसम की वजह से मंच तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन फोन पर दिए गए उनके संबोधन ने साफ कर दिया कि कांग्रेस अब चुनावी मोड में आ चुकी है। दूसरी ओर बीजेपी भी संगठन और सरकार के दम पर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है।